19.4.2015
AMAR UJALA

'चीनी उत्पादन व खपत में संतुलन जरूरी'

- लखनऊ विवि में आयोजित सेमिनार में वक्ताओं ने दिए सुझाव
- गन्ने से इथेनॉल बनाने की मंजूरी दे सरकार : प्रो मोहन

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। चीनी उत्पादन व खपत में संतुलन कायम किए बिना उत्तरी भारत में चीनी उद्योग के संकट को खत्म नहीं किया जा सकता। सरकार को गन्ने से इथेनॉल बनाने की मंजूरी देने पर विचार करना चाहिए। इससे चीनी के दामों में गिरावट को रोका जा सकता है। ये बातें नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने कहीं। वे शनिवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में नॉर्थ इंडियन शुगरकेन एंड शुगर टेक्नोलॉजिस्ट्स एसोसिएशन की ओर से 'उत्तर भारत में शुगर इंडस्ट्री का संकट : समस्याएं व संभावनाएं' विषय पर आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि दुनिया में इस समय मांग से ज्यादा चीनी की उपलब्धता है। गन्ने से चीनी के बजाय इथेनॉल बनाकर इस समस्या से निपटा जा सकता है। चीनी बनाते समय गन्ने से करीब 4.5 फीसदी ही शीरा निकलता है। वर्ष 2017 तक पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल की ब्लैंडिंग होनी है। शीरे से इथेनॉल बनाकर इस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि शुगर रिकवरी के लिहाज से भारत कई देशों से पीछे है। इस तरफ भी ध्यान देना होगा। उन्होंने शुगर रिकवरी के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। शुगर इंडस्ट्री को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि वह रंगराजन समिति की सिफारिशों से इतर भी दूसरे विकल्पों पर विचार करे। लखनऊ विवि के कुलपति प्रो. एसबी निम्से ने कहा कि महाराष्ट्र में ड्रिप इरीगेशन से गन्ने की उत्पादकता 35 फीसदी तक बढ़ाई जा सकती है। यूपी में भी इस दिशा में काम होना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ शुगरकेन रिसर्च लखनऊ के पूर्व निदेशक एस सोलोमन ने कहा कि पश्चिमी यूपी में जमीन की उर्वरा शक्ति गिरी है। इस तरफ ध्यान देना होगा। सेवानिवृत्त अपर गन्ना आयुक्त डॉ. राममूर्ति सिंह ने कहा कि शुगर इंडस्ट्री ही नहीं किसान भी संकट में हैं। ऐसे में प्रदेश और केंद्र सरकार को आगे आकर रास्ता निकालना चाहिए। सेमिनार के दूसरे सत्र में ग्रुप डिस्कसन भी हुआ।

लखनऊ विवि में शनिवार को 'उत्तर भारत में शुगर इंडस्ट्री का संकट : समस्याएं व संभावनाएं' विषय पर आयोजित सेमिनार में मौजूद लोग।

कंपनियों को सस्ती चीनी देना गलत

बलरामपुर चीनी मिल समूह के ग्रुप हेड (ऑपरेशंस) केपी सिंह ने कहा कि प्रदेश में शुगर इंडस्ट्री की बदहाली के लिए खुद चीनी मिलें जिम्मेदार हैं। चीनी के दामों में गिरावट से चीनी मिलों का संकट बढ़ा है। फिर भी कुछ चीनी मिलों ने 90 फीसदी भुगतान किया और कुछ ने बिल्कुल भी नहीं किया। चीनी के दाम गिरने के बाद भी 200-220 रुपये क्विंटल की दर से तो मिलें भुगतान दे सकती है। उन्होंने कहा कि चीनी उत्पादन का 10 फीसदी ही घरेलू उपभोक्ताओं को जाता है। 80 फीसदी चीनी का उपयोग कोल्ड ड्रिंक कंपनियां, बिस्किट निर्माता और मिठाई बनाने वाले करते हैं। किसानों की कीमत पर उन्हें सस्ती चीनी दी जा रही है। चीनी के रेट 60 रुपये हो या 20 रुपये कोल्ड ड्रिंक या मिठाई के भाव वही रहेंगे। इस पर सरकार को सोचना चाहिए।

इथेनॉल और शुगर कांप्लेक्स पर करेंगे विचार : जेटली

वाह्य सहायतित परियोजनाओं व एनआरआई विभाग के सलाहकार मधुकर जेटली ने कहा कि गन्ना मूल्य भुगतान को चुनौती के रूप में देखना होगा। गन्ना मूल्य अदा कराने के लिए हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए हैं, सरकार को उनका अनुपालन सुनिश्चित करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चीनी उद्योग और किसानों की समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा।

Media/Lko/71/2015